Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

अक्तूबर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- बिहार में जारी हुआ जातीय आधारित सर्वेक्षण 3
- बिहार के सहरसा में खुलेगा जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग 4
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कारा उद्योग के ब्रांड 'मुक्ति' का किया अनावरण 4
- किशनगंज की रौशनी परवीन विश्व युवा सम्मेलन 2023 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व 6
- पटना देश का दूसरा और मुज़फ्फरपुर तीसरा प्रदूषित शहर 7
- कृषि में मुज़फ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर 7
- दो दिवसीय ट्रैवेल और टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) 2023 9
- पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन, किशोर कुणाल और सुधा वर्गीज़ को बनाया गया सदस्य 10
- भीम संसद रथ 11
- बिहार ने जीती सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 11
- आशा कार्यकर्त्ता कल्पना कुमारी व सेविका ललिता कुमारी को मिला सम्मान 12
- बिहार के 10 ज़िलों में बनाए जाएंगे सीड हब 14
- लोकनृत्य प्रतियोगिता में भोजपुर टीम बनीं विजेता 14
- आकांक्षी ज़िलों में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने के मामले में पूर्णिया ज़िला शीर्ष पर 15
- बरौनी रिफाइनरी को मिला सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार 16
- बिहार में तीन नए पावर सब स्टेशन का होगा निर्माण 17
- फ्रांस के इंस्टीट्यूट व आईआईटी पटना के मध्य अकादमिक सहयोग के लिये समझौता 18
- मनेर (पटना) की शिप्रा को मिला मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब 19
- बिहार में 'गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना' की शुरुआत 19
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ 19
- महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं राष्ट्रपति 21
- बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवज़ा 21
- जेटीबीएस योजना 22
- बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान 23
- बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने पैरा एशियन गेम्स 2023 के हाई जंप स्पर्द्धा टी 63 में जीता स्वर्ण पदक 24
- बिहार के 15 शिल्प कलाकार वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 मेधा पुरस्कार से सम्मानित 25
- बिहार में शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्कूल से कट गया लाखों बच्चों का नाम 26
- बिहार में इथेनॉल के लिये मक्का उत्पादन पर ज़ोर, 100 फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य 28
- नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना मंज़ूर 29
- युवाओं को रोज़गार दिलाने में भागलपुर पूरे प्रदेश में शीर्ष पर 30
- बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी राज्य सरकार 30
- मुज़फ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में खुलेगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र 31
- बिहार के शशि भूषण ने 37वें नेशनल गेम्स में जीता रजत पदक 31
- कॉर्डियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का दो दिवसीय 29वाँ वार्षिक सम्मेलन 32
- मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी स्व. रामबहादुर सिंह और स्व. पद्मानंद सिंह 'ब्रह्मचारी' की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण 33

नोट :

बिहार

बिहार में जारी हुआ जातीय आधारित सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर आ गया है। पहले पायदान पर असम और दूसरे पायदान पर झारखंड है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार असम में कुल उपभोक्ताओं में सबसे अधिक 93 फीसदी घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जबकि दूसरे पायदान पर रहे झारखंड में 92.6 फीसदी उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं।
- वहीं बिहार में उत्तर बिहार (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) में 92.1 फीसदी तो दक्षिण बिहार (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) में 86.8 फीसदी घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं।
- अन्य राज्यों में जहाँ बिजली की खपत कम हो गई थी वहीं बिहार में यह खपत बढ़ गई। लोगों ने घरों में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का खूब इस्तेमाल किया।
- उत्तर बिहार में शहरी उपभोक्ता मात्र 16 फीसदी जबकि दक्षिण बिहार में 29 फीसदी हैं। ग्रामीण इलाकों में उत्तर बिहार में 84 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 71 फीसदी उपभोक्ता हैं। गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में उत्तर बिहार में छह फीसदी तो दक्षिण बिहार में 7.7 फीसदी हैं।
- औद्योगिक कनेक्शन में उत्तर बिहार में 0.6 फीसदी तो दक्षिण बिहार में एक फीसदी उपभोक्ता हैं। कृषि कनेक्शन में उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में इसकी संख्या अधिक है। उत्तर बिहार में मात्र 1.1 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 4.4 फीसदी कृषि कनेक्शन हैं, जबकि अन्य श्रेणी में उत्तर बिहार में 0.2 फीसदी तो दक्षिण बिहार में 0.4 फीसदी कनेक्शन हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल औसतन छह लाख बिजली उपभोक्ताओं की वृद्धि होने का अनुमान है।

नोट :

बिहार के सहरसा में खुलेगा जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग

चर्चा में क्यों ?

1 अक्तूबर, 2023 को सहरसा ज़िले के जीविका परियोजना प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत मखाना उद्योग का केंद्र सहरसा में स्थापित होगा।

प्रमुख बिंदु

- मखाना उद्योग लगाने के लिये 2 करोड़ 33 लाख 91 हज़ार रुपए की स्वीकृति मिली है। जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के तहत मखाना उद्योग संचालित होगा, जो मखाना का सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में जाना जाएगा।
- डीएम वैभव चौधरी ने बताया कि मखाना प्रसंस्करण उद्योग में नॉर्मल (सामान्य) किस्म के मखाना की प्रोसेसिंग कर उसे उत्कृष्ट किस्म का बनाया जाएगा। उसकी पैकेजिंग कर ब्रॉंडिंग की जाएगी। मखाना से बने गुणवत्तापूर्ण विभिन्न किस्म के उत्पादों को देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा।
- उत्पाद इस तरह के बनाए जाएंगे जिसकी बाज़ार में अलग पहचान हो और इसे देखते ही लोग खरीद लें। जीविका के ज़िला औद्योगिक स्तर की पैकेजिंग कर मखाना की आपूर्ति देश-विदेश में की जाएगी तथा डिजाइन व जाँच केंद्र के अलावा कच्चा माल डिपो की भी स्थापना होगी।
- इन केंद्रों पर नई तकनीक से गुणवत्तापूर्ण मखाना उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण देकर किसानों का कौशलवर्धन किया जाएगा।
- प्रसंस्करण उद्योग जीविका के द्वारा दरभंगा और कटिहार ज़िले में भी खाना प्रसंस्करण उद्योग खोलने की योजना है। ज़िले के आसपास के ज़िलों को यहाँ से जोड़कर मखाना की पैकेजिंग सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इन प्रखंड क्षेत्र के 500 मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोड्यूसर ग्रुप में जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कारा उद्योग के ब्रांड 'मुक्ति' का किया अनावरण

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारा उद्योग के ब्रांड 'मुक्ति' का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- संग्रहालय में जेल में कैदियों द्वारा निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। बिहार की जेलों में बंद कैदी 100 से अधिक सामग्री का निर्माण कर रहे हैं।

नोट :

- इसमें मसाला, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती वस्त्र, खादी वस्त्र, काष्ठ उद्योग, हस्तशिल्पमुद्रण सामग्री, चप्पल उद्योग, होम केयर, खाद्य, लौह, कागज़ आदि सामग्री का उत्पादन किया जाता है।
- इस समय बिहार की 8 केंद्रीय व 2 मंडल काराओं (कुल 10 जेलों) में कारा उद्योग संचालित हैं। इसके द्वारा करीब 1000 सश्रम सज़ावार बंदियों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। इसके लिये बंदियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
- बिहार की जेलों में 'एक जेल-एक उत्पाद' की योजना पर काम हो रहा है। इस योजना में 33 मंडल कारा और 17 उप काराओं को शामिल करने की योजना है। यहाँ कारा उद्योग स्थापित किया जाएगा।
- कारा महानिरीक्षक ने बताया कि कारा उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बंदियों के अपराध से पीड़ित परिवार के कल्याणार्थ खर्च किया जाता है, साथ ही इसका कुछ हिस्सा बंदी कल्याण कोष में जाता है।
- प्रदर्शनी में आदर्श केंद्रीय कारा, बेऊर, पटना, केंद्रीय कारा, बक्सर, केंद्रीय कारा, मोतिहारी, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा, मुज़फ्फरपुर, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, भागलपुर, विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर, केंद्रीय कारा, गया, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ एवं मंडल कारा, छपरा से बंदियों द्वारा निर्मित विभिन्न सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया है।

नोट :

किशनगंज की रौशनी परवीन विश्व युवा सम्मेलन 2023 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज ज़िले की सामाजिक कार्यकर्त्ता रौशनी परवीन नवंबर माह में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

प्रमुख बिंदु

- विश्व युवा सम्मेलन में मात्र 6 युवाओं का चयन पूरे विश्व भर में हुआ है। रौशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी होंगी।
- 16 नवंबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में यंग एक्टिविस्ट समिट में बतौर स्पीकर भाषण देंगी, जहाँ से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रसारण इंस्टाग्राम चैनल पर भी किया जाएगा।
- विदित है कि यूएन की टीम ने किशनगंज महिला हेल्पलाइन कार्यालय आकर रौशनी परवीन द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली थी।
- गौरतलब है कि किशनगंज प्रखंड के सिमलबाड़ी निवासी रौशनी परवीन बाल सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के कार्यक्रम और यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। वह जनवरी 2023 से स्वतंत्र रूप से बाल संरक्षण के मुद्दे पर सक्रियता से कार्य कर रही हैं।
- इन्होंने बाल विवाह को रोकने, ड्रॉपआउट बच्चियों को स्कूलों से जोड़ने में काफी मेहनत की है।

नोट :

पटना देश का दूसरा और मुज़फ्फरपुर तीसरा प्रदूषित शहर

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को जारी रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजधानी पटना देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, वहीं तीसरे नंबर पर मुज़फ्फरपुर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक, पटना 97.7 माइक्रो/घनमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन पिछले वर्ष यहाँ वायु गुणवत्ता में 24 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
- ध्यान देने योग्य है कि इन शीर्ष 10 शहरों में सात शहर दिल्ली-एनसीआर और बिहार के हैं, जो गंगा के मैदानी भाग का हिस्सा हैं।
- क्लाईमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला के अनुसार इस विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में गंगा के मैदानी शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- हालाँकि, भारी प्रदूषण को देखते हुए इन शहरों में देश में सबसे अधिक पीएम स्तर का अनुभव जारी है। इसलिये प्रदूषण बढने के कारणों की पड़ताल किया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

कृषि में मुज़फ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को नीति आयोग ने देश के 112 आंकाक्षी ज़िलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार का मुज़फ्फरपुर ज़िला कृषि के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- कृषि के क्षेत्र में लगातार सुधार ने आकांक्षी ज़िलों में मुजफ्फरपुर को पहली रैंकिंग पर पहुँचाया है।
- ओवरऑल रैंकिंग में देश में इस बार मुजफ्फरपुर ज़िले को छठा स्थान मिला है। शिक्षा में 100वीं व स्वास्थ्य में 26वीं रैंक पर है। शिक्षा में ज़िला लगातार नीचे फिसलता गया है और दो साल में इस बार इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।

नोट :

- आंकाक्षी ज़िलों के तहत मुजफ्फरपुर में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,फाइनेंसियल एंड स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में लगतार उपलब्धियाँ हासिल हुई थीं।
- दिसंबर 2020 से लेकर 2021 तक ज़िला शीर्ष स्थान में 1 से लेकर 10 में रहा। इसके बाद 20वें और 64वें नंबर तक जा पहुँचा।
- इस बार न केवल रैंकिंग 100वें नंबर पर फिसल गई है बल्कि स्कोरिंग में भी कमी आई है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्कोर एक फीसदी नीचे चला गया है।

नोट :

दो दिवसीय ट्रैवेल और टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) 2023

चर्चा में क्यों ?

7-8 अक्तूबर, 2023 को पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय ट्रैवेल और टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) -2023 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- दो दिनों के इस मंथन में बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। समारोह के अंतिम सत्र में बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।
- समापन सत्र से पहले 'आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाएँ : ध्यान, योग, स्वास्थ्य' विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ।
- कार्यक्रम में बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के प्रोटोकॉल अधिकारी राहुल देव ने बताया कि बोधगया में मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में इस सत्र से पहला कोर्स शुरू होगा।
- पर्यटन निगम के निदेशक नंद किशोर ने कहा कि बिहार आध्यात्मिक राजधानी है। विश्व में तीन महत्त्वपूर्ण जगह हैं- वेटिकन सिटी, मक्का व बोधगया। इन तीनों में एक बिहार में है, जहाँ पूरे विश्व से पर्यटक पहुँचते हैं।
- इस कार्यक्रम में निम्न पुरस्कार दिये गए-
  - बेस्ट प्रिंट प्रोमोशनल मैटेरियल अवॉर्ड: इंडिया टूरिज्म, छत्तीसगढ़ टूरिज्म और झारखंड टूरिज्म
  - पार्टनर होटल अवॉर्ड: होटल चाणक्या व होटल एवीआर पटना
  - ट्रांसपोर्ट पार्टनर: पॉपुलर टूअर्स
  - ग्रुप पार्टिसिपेशंस अवॉर्ड: एबीटीओ व टीएबी
  - मोस्ट इनोवेटि व प्रोडक्ट: रिया ट्रेवल्स एंड टूर
  - बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड (छोटा पैवेलियन): हरियाणा टूरिज्म
  - बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड: टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड व तामिलनाडु टूरिज्म
  - बेस्ट डेकोरेशन अवॉर्ड (बड़ा पैवेलियन): उत्तर प्रदेश टूरिज्म
  - मोस्ट प्रोमिशिंग डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर्स एंड स्प्रीचुअल टूरिज्म: बिहार टूरिज्म

नोट :

पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन, किशोर कुणाल और सुधा वर्गीज़ को बनाया गया सदस्य

चर्चा में क्यों ?

6 अक्तूबर, 2023 को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल एम. पंचोली की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया। इस आठ सदस्यीय समिति में आचार्य किशोर कुणाल समेत तीन गैर-पदेन सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित तीन गैर-पदेन सदस्यों में पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर को शामिल किया गया है। अन्य दो सदस्यों में समाजसेवी सुधा वर्गीज़ और सेवानिवृत्त ज़िला जज ओम प्रकाश शामिल हैं।
- समिति में महाधिवक्ता समेत कुल तीन पदेन सदस्य होंगे। दो अन्य पदेन सदस्यों में पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह एवं पटना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह शामिल हैं।
- सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। समिति में अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत कुल 8 सदस्य होंगे।
- समिति पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करती है। इस पैनल के अधिवक्ताओं की सेवा उन ज़रूरतमंदों तक नि:शुल्क पहुँचाई जाती है, जो गरीबी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते।

नोट :

भीम संसद रथ

चर्चा में क्यों ?

10 अक्तूबर, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 'संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ देश बचाओ' रथ को भीम संसद रथ के नाम से रवाना किया।
- भीम संसद रथ के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श, विचार एवं उनके द्वारा किये गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा।
- भीम संसद का आयोजन 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित किया जाएगा।

बिहार ने जीती सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

10 अक्तूबर, 2023 को बिहार ने सब जूनियर बालक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप टियर-2 का खिताब अपने नाम कर लिया।

प्रमुख बिंदु

- आंध्र प्रदेश में खेले गए मैच में आयुष कुमार (कप्तान) के एकमात्र गोल की मदद से बिहार की टीम ने दिल्ली को 1-0 से पराजित किया।
- इसके पहले सेमीफाइनल में बिहार ने असम को हराया था।
- इस मैच में आयुष कुमार (कैप्टन), श्रवण कुमार (गोलकीपर), अजीत कुमार, मकसद अंसारी, राजकरण कुमार, अजय कुमार, विक्रम कुमार, आलोक कुमार, निलेश कुमार, करण, हिंबाराम, विक्रम राजवंशी टीम मेंबर थे।

नोट :

आशा कार्यकर्त्ता कल्पना कुमारी व सेविका ललिता कुमारी को मिला सम्मान

चर्चा में क्यों ?

10 अक्तूबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार की दो महिलाओं आशा कार्यकर्त्ता कल्पना कुमारी व सेविका ललिता कुमारी को सम्मानित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बिहार की आशा कार्यकर्त्ता कल्पना व सेविका ललिता कुमारी ने अतिगंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन एवं रिफरल सेवा प्रदान करने के लिये उत्कृष्ट कार्य किये हैं।
- सेविका ललिता कुमारी भागलपुर की एवं आशा कार्यकर्त्ता कल्पना कुमारी खगड़िया की निवासी हैं।

नोट :

बिहार के 10 ज़िलों में बनाए जाएंगे सीड हब

चर्चा में क्यों ?

11 अक्तूबर, 2023 को बिहार कृषि विभाग ने प्रदेश के 10 ज़िलों में सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति दे दी। इन ज़िलों में गेहूँ, दलहन और तिलहन के बीज का उत्पादन होगा।

प्रमुख बिंदु

- पहले चरण में 3125 एकड़ में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिये खेती कराई जाएगी। संबंधित ज़िले के सहायक निदेशक (शष्य) सीड हब के लिये गाँव या पंचायत का चयन करेंगे।
- चयनित गाँव के किसान या किसान समूह के ज़रिये यहाँ बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग की देखरेख में होगा।
- विभाग ने इसके लिये किसानों को बीज पर 80 फीसदी अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर किसानों को तीन साल तक मदद (रिवाल्विंग फंड) की जाएगी। मदद के रूप में मिलने वाली राशि किसानों को लौटानी होगी।
- गौरतलब है कि चौथे कृषि रोड मैप में राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिये अगले पाँच साल में 100 सीड हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें रबी मौसम में दस सीड हब बनाए जाएंगे।
- इसमें 683.75 क्विंटल बीज बाँटे जाएंगे। इसके माध्यम से 16375 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल नए गाँव या पंचायत में सीड हब बनाए जाएंगे।
- ज़िलेवार फसलों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है- गया में गेहूँ, चना और मूंग, वैशाली में गेहूँ मसूर और मूंग, भागलपुर में गेहूँ, राई, सरसों और मूंग, नालंदा में गेहूँ, मसूर और मूंग, बेगूसराय में गेहूँ और राई, समस्तीपुर में गेहूँ, मसूर और मूंग, पटना में गेहूँ, राई, सरसों और मूंग, नवादा में गेहूँ, मसूर और मूंग, दरभंगा में गेहूँ, मसूर और मूंग तथा पूर्णिया में गेहूँ, मसूर और मूंग का सीड हब बनेगा।
- गेहूँ के लिये सीड हब का रकबा न्यूनतम 125 एकड़ और दलहन-तिलहन के लिये 62.5 एकड़ होगा।

लोकनृत्य प्रतियोगिता में भोजपुर टीम बनीं विजेता

चर्चा में क्यों ?

11 अक्तूबर, 2023 को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में उच्च विद्यालय कहारी, भोजपुर की टीम विजेता बनीं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भोजपुर की विजेता टीम अब राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में शामिल होगी। वहीं दूसरे स्थान पर उच्च विद्यालय नवादा एकमा (सारण) की टीम रही। तीसरे स्थान पर रूंगटा बालिका उच्च विद्यालय नवगछिया, भागलपुर की टीम रही।
- कार्यक्रम का उद्घाटन एससीईआरटी डायट की संयुक्त निदेशक डॉ. रश्मि प्रभा, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र के परियोजना समन्वयक अमिताभ और एससीईआरटी के जनसंख्या शिक्षा कोषांग की विभाग प्रभारी डॉ. विभा रानी ने किया।
- प्रतियोगिता का विषय बालक और बालिका के लिये समान अवसर, नशाखोरी निवारण, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ संबंध, बाल विकास में संयुक्त परिवार की भूमिका और पर्यावरण की रक्षा रखा गया था।
- इस राज्यस्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में कुल 8 प्रतियोगिता में राज्य के 18 ज़िलों की प्रतिभागी टीमें शामिल हुईं।

आकांक्षी ज़िलों में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने के मामले में पूर्णिया ज़िला शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

12 अक्तूबर, 2023 को बैंकर्स समिति से राज्य सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी ज़िलों में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने के मामले में पूर्णिया ज़िला शीर्ष पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- लक्षित वित्तीय समायोजन एकीकृत कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) के दूसरे चरण के तहत बिहार के आकांक्षी ज़िलों में एकीकृत कार्यक्रम के तहत लक्षित समूह तक बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाई जाती हैं। उसके माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
- वित्त विभाग ने बताया कि औरंगाबाद, नवादा और पूर्णिया में अटल पेंशन योजना की उपलब्धि दो सौ प्रतिशत से भी अधिक रही है। इसमें सबसे कम उपलब्धि 131 प्रतिशत मुज़फ्फरपुर की रही है।
- 231 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ पूर्णिया शीर्ष पर रहा है। शेखपुरा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की उपलब्धि 111 प्रतिशत रही है। इस योजना में सबसे खराब प्रदर्शन मात्र 58 प्रतिशत सीतामढ़ी ज़िला का रहा है।
- जबकि अररिया, बेगूसराय, जमुई, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया और शेखपुरा में जीवन ज्योति बीमा योजना की उपलब्धि सौ प्रतिशत से अधिक पाई गई। समग्रता में सभी आकांक्षी ज़िलों की उपलब्धि बेहतर रही है।

नोट :

- गौरतलब है कि बिहार के 13 ज़िले आकांक्षी ज़िलों में शामिल हैं। इनमें अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुज़फ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी हैं। इन सभी ज़िलों में बैंकिंग सुविधा से वंचित नागरिकों का खाता खोलने के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित था।

बरौनी रिफाइनरी को मिला सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) ने बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित बरौनी रिफाइनरी को 09 एमएमटीपीए से कम क्षमता की श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 9-11 अक्तूबर तक नई दिल्ली में सीएचटी द्वारा आयोजित 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य, निदेशक (रिफाइनरीज़) शुक्ला मिस्त्री एवं बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आर.के. झा को यह पुरस्कार प्रदान किया।
- 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का विषय 'उभरती ऊर्जा प्रवृत्तियाँ और रिफाइनिंग का भविष्य' था और इसमें दुनिया भर के लगभग 1400 प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने भाग लिया।
- पुरस्कार का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2022-23 के लिये सात महत्त्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित था।
- बरौनी रिफाइनरी ने 2022-23 के दौरान क्रूड थ्रुपुट 6785.40, एमबीएन 71.24, परिचालन उपलब्धता 99.90 प्रतिशत, परिचालन लागत 1.92 डॉलर/बीबीएल, विशिष्ट भाप खपत 0.90, ऊर्जा संरक्षण उपाय 18807 एसआरएफटी/वर्ष, विशिष्ट जल खपत 0.83 तथा कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 1459.50 टीएमटी सहित सभी पैरामीटर पर देश में नौ एमएमटीपीए से कम क्षमता वाली सभी रिफाइनरियों से बेहतर प्रदर्शन किया।
- गौरतलब है कि इंडियन ऑयल की एक राज्य स्वामित्व वाली बरौनी रिफाइनरी का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ 49.40 करोड़ रुपए की लागत से 1964 में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष शोधन की क्षमता के साथ किया गया था। 15 जनवरी, 1965 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री डॉ. हुमायूँ कबीर द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
- गौरतलब है कि मई 2022 में बरौनी रिफाइनरी में ऊर्जा कुशल संचालन की दिशा में एक नई पहल के रूप में, भारत का पहला और दुनिया का तीसरा ग्रीन कूलिंग टॉवर कमीशन किया गया था।

नोट :

बिहार में तीन नए पावर सब स्टेशन का होगा निर्माण

चर्चा में क्यों ?

15 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर वैशाली, बेगूसराय और बिहारशरीफ में करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से तीन नए पावर सब स्टेशन (पीएसएस) का निर्माण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- तीनों पावर सब स्टेशन (पीएसएस) में दस मेगावाट (एमवीए) क्षमता के दो-दो पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित होंगे। इसके साथ ही आधा दर्जन ज़िलों में नवनिर्मित ग्रिडों से पावर सब स्टेशनों को जोड़ने पर 46 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।
- बिजली कंपनी के अनुसार नालंदा ज़िले के रामचंद्रपुर (बिहारशरीफ) सुपरग्रिड कैंपस में 14.73 करोड़ रुपए लागत से जीआईएस आधारित पीएसएस का निर्माण किया जाएगा।
- वैशाली प्रखंड के ग्रिड कैंपस में ही 10.032 करोड़ रुपए की लागत से नया पीएसएस स्थापित किया जाएगा। वहीं बेगूसराय ज़िला स्थित भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर गाँव में 11.98 करोड़ रुपए की लागत से नए सब स्टेशन की मंज़ूरी मिली है।
- विदित हो कि बिजली कंपनियों ने बिजली की बढ़ी मांग को देखते हुए कई नए ग्रिड का निर्माण किया है। अब उन ग्रिडों को पुराने पावर सब स्टेशनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको ओवरलोडेड होने से बचाया जा सके। इससे संबंधित क्षेत्रों को 24 घंटे निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली अस्पताल, अनुमंडलीय न्यायालय एवं उपकारा पालीगंज आदि प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा सकेगी।

नोट :

फ्रांस के इंस्टीट्यूट व आईआईटी पटना के मध्य अकादमिक सहयोग के लिये समझौता

चर्चा में क्यों ?

14 अक्तूबर, 2023 को आईआईटी पटना और फ्राँस के इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज (टूलूज आईएनपी) के मध्य अकादमिक सहयोग के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच सिंबायोटिक संबंधों को बेहतर करने के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- समझौता ज्ञापन पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टी. एन. सिंह, डॉ. आसिफ इकबाल एसोसिएट डीन, रिसोर्सेज आईआईटी पटना, डॉ. राजू हलदर एसोसिएट प्रोफेसर (सीएसई) आईआईटी पटना और प्रोफेसर पास्कल मौसिवन, उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूनिवर्सिटी डेटूलूड, फ्राँस द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- यह समझौता दोनों संस्थान ने आपसी हित के विषयों पर विभिन्न अल्पकालिक कार्यक्रमों के लिये शैक्षणिक, प्रशासनिक कर्मचारियों और छात्रों के आदान-प्रदान को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिये किया है।
- इसके अलावा इससे एक-दूसरे के संकाय/छात्रों/विद्वानों को अनुसंधान की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। इसमें शामिल तथा चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिये प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्यक्रम होने के लिये आमंत्रित करने पर सहमति बनी।
- इससे आईआईटी पटना प्रभावशाली अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भारत और फ्राँस लंबे समय से सांस्कृतिक, व्यापार और आर्थिक संबंध साझा करते रहे हैं।

नोट :

मनेर (पटना) की शिप्रा को मिला मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब

चर्चा में क्यों ?

16 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मनेर (पटना) की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित '46वें मिसेज यूनिवर्स'में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जाता है।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रतियोगिता एक अक्तूबर से शुरू हुई थी और आठ अक्तूबर को उन्हें इस खिताब से नवाजा गया था।
- 91 देशों की प्रतिभागियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर शिप्रा सिंह ने यह खिताब हासिल किया है।
- इससे पहले अप्रैल में 'द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट'में वह दूसरी रनरअप रहीं थीं। इसी आधार पर उन्हें प्रतियोगिता में जगह मिली थी।
- जिस भारतीय परिधान को पहन शिप्रा सिंह रैंप पर उतरीं, उसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था।

बिहार में 'गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना' की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

17 अक्तूबर, 2023 को बिहार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिये 'गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना' की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- कला संस्कृति मंत्री ने बताया कि इस योजना में आठ से 14 वर्ष तक के प्रशिक्षु खिलाड़ियों को खेल विद्या में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस योजना की सहायता से बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- गैर-आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना में निबंधित खिलाड़ी खेल प्रशिक्षण के निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक ज़िले में इस योजना का संचालन होगा। पंचायतों, प्रखंड, ज़िलों के मुख्य आउटडोर स्टेडियम, ज़िला खेल भवन, खेल मैदान व स्कूलों में इस योजना का संचालन होगा। प्रत्येक कार्य दिवस को चार घंटे की प्रशिक्षण अवधि रहेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

18 अक्तूबर, 2023 को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के बापू सभागार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28) का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 में राज्य के पहले कृषि रोडमैप की शुरुआत की गई थी। दूसरे कृषि रोडमैप का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा तथा तीसरे कृषि रोड का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया।

नोट :

- बिहार में कृषि रोडमैप से किसानों को काफी फायदा हुआ है। धान, मक्का, गेहूँ और आलू का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ी है। वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक पहले कृषि रोडमैप के तहत कार्य किये गए। वर्ष 2011-12 में नालंदा के एक किसान ने प्रति हेक्टेयर धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले प्रति हेक्टेयर का रिकॉर्ड चीन के नाम था। आलू के उत्पादन में भी नालंदा ज़िले के एक गाँव ने विश्व कीर्तिमान बनाया।
- वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक दूसरे कृषि रोडमैप के तहत कार्य किये गए, जिसके फलस्वरूप फल, सब्जी, दूध, अंडा एवं मछली का उत्पादन काफी बढ़ा है। उत्पादकता बढ़ने से किसानों को काफी फायदा हुआ है।
- वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक तीसरे कृषि रोडमैप के अंतर्गत कार्य तय किये गए थे, लेकिन इसका कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ाकर वर्ष 2023 तक कर दिया गया। बचे हुए कार्य एवं आगे के कार्य और विस्तार को लेकर चतुर्थ कृषि रोडमैप की शुरुआत की गई है। इसके तहत तेज़ी से कार्य होंगे, ताकि किसानों को और फायदा हो सके।
- बिहार में मछली का उत्पादन ढाई गुना बढ़ा है। अब बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। चावल, गेहूँ और मक्का के उत्पादन को लेकर बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। आलू, गोभी, बैंगन और टमाटर का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। बिहार में मखाना का भी उत्पादन काफी बढ़ा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोडमैप में कृषि के साथ-साथ पशुओं की उचित देखभाल के लिये भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल खोला जा रहा है, ताकि पशुओं की उचित देखभाल और इलाज हो सके। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा चौर क्षेत्र है। वहाँ वर्ष में 9 महीना पानी लगा रहता है। 9 लाख हेक्टेयर भूमि चौर क्षेत्र है। कृषि रोडमैप के तहत ऐसे 6 ज़िलों के लिये योजना की शुरुआत की गई है।
- चतुर्थ कृषि रोडमैप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये मंत्रिमंडल ने 1 लाख 62 हज़ार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। राज्य में 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। चतुर्थ कृषि रोडमैप में सभी बातों का ध्यान रखा गया है और इसे बहुत व्यापक बनाया गया है। इससे न सिर्फ उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इससे राज्य को भी फायदा होगा।

नोट :

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं राष्ट्रपति

चर्चा में क्यों ?

19 अक्तूबर, 2023 को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के प्रेक्षागृह में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति ने सबसे पहले दीक्षांत समारोह में प्रसिद्ध उद्योगपति, लेखक एवं सामाजिक विचारक आर.के. सिन्हा एवं भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखक चंद्रप्रकाश द्विवेदी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
- राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के विभिन्न संकायों स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पासआउट विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र भेंटकर कुलाधिपति स्वर्ण पदक की उपाधि से सम्मानित किया।
- दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने बेतिया और शिवहर में विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख रुपए का मुआवज़ा

चर्चा में क्यों ?

21 अक्तूबर, 2023 को बिहार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरएस भटे ने पटना स्थित विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप 5) परिसर में पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम में बताया कि राज्य के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले मुआवजे की राशि महज़ दो लाख रुपए थी।

प्रमुख बिंदु

- यह निर्णय पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिये लिया गया है और जल्द-से-जल्द यह राशि शहीद के आश्रितों को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
- पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने की स्थिति में यह राशि देय नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ ही बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी इस तरह का लाभ मिल सकेगा। पुलिस मुख्यालय की पहल पर करीब लाखों पुलिसकर्मियों को इस लाभ से जोड़ा गया है।

नोट :

- छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की यह राशि दी जाएगी। वहीं, उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामलों में भी यह राशि दी जाएगी।
- डीजीपी ने बिहार पुलिस की आवासन और ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में बदलाव की घोषणा भी की है। बिहार पुलिस के पदाधिकारी व कर्मियों के निजी जीवन और कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर जल्द ही यह बदलाव पूरे कर लिये जाएंगे।
- राज्य सरकार एक विधिवत आवासन नीति पर काम कर रही है, ताकि जो भी पदाधिकारी-कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके परिवार-बच्चे एक स्थान पर रह कर पढ़ाई कर सकें और सामान्य जीवन जी सकें।
- बिहार पुलिस का दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति में भी बदलाव किया जा रहा है, ताकि आपकी परिवार के प्रति निजी जिम्मेदारियाँ और कर्त्तव्य के प्रति ज़िम्मेवारी में संतुलन बना रहे। महिलाओं की संख्या भी जो एक-तिहाई होने जा रही है, उसको देखते हुए भी नीति में बदलाव आवश्यक है।
- विदित है कि हर वर्ष 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।
- 21 अक्तूबर 1959 को भारत-चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊँचाइयों पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक टेकरी पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा किये गए हमले में 10 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 1961 में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हर साल 21 अक्तूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा, तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

जेटीबीएस योजना

चर्चा में क्यों ?

20 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल ने बेरोज़गार युवाओं के लिये जेटीबीएस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत रेलवे समस्तीपुर सहित कुल 28 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इन स्टेशनों पर जेटीबीएस के माध्यम से लोग अनारक्षित टिकट काट सकेंगे। इसके अलावा मासिक सीज़न टिकट व प्लेटफॉर्म टिकट काटने की भी सुविधा उन्हें मिलेगी। आसपास के स्टेशनों को इसके लिये चयनित किया गया है।
- चयन प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साफ-सुथरी छवि के युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिये समस्तीपुर रेल मंडल आवेदन लेगा। कमीशन के आधार पर इनका भुगतान किया जाएगा।
- विदित है कि वर्तमान में प्रति टिकट 2 व मासिक सीज़न टिकट पर 5 रुपए का भुगतान रेलवे की ओर से निर्धारित है।

नोट :

- जेटीबीएस योजना के लिये समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, सुगौली, बगहा, बैरगनिया, लहेरियासराय, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, रुसेरा घाट, सिमरी बख्तियारपुर, चकिया, हरनगर, बनमनखी, सकरी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज, हसनपुर रोड और मोतीपुर स्टेशन शामिल हैं।

बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 22 अक्तूबर, 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर बीआईए सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मान समारोह आयोजन बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम व मेडिवर्सल फाउंडेशन की ओर से बीआईए सभागार में किया गया।
- कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चिकित्सा, सेवा, शिक्षा, समाजसेवा एवं राजनीति में बेहतर कार्य करने वाले प्रदेश के इन दिग्गज विभूतियों को उनकी कर्मठता एवं विशिष्ट सेवा भावना के लिये सम्मानित किया।
- केसरी सम्मान से सम्मानित होने वाले विभूतियाँ-
- लोकगायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉ. शांति राय, पद्मश्री डॉ. विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर, डॉ. अजय कुमार, डॉ. सत्यजीत सिंह, केपीएस केसरी, डॉ. सहजानंद सिंह, विपिन सिंह, डॉ. अर्जुन सिंह, डॉ. विमल कारक, डॉ. अमूल्य सिंह, ओपी अग्रवाल, डॉ. एसएन सिन्हा, एन अग्रवाल तथा डॉ. गुरुदेव।

नोट :

बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने पैरा एशियन गेम्स 2023 के हाई जंप स्पर्द्धा टी 63 में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा मे क्यों ?

24 अक्तूबर, 2023 को पैरा एशियाई गेम्स में बिहार के जमुई ज़िले के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्द्धा टी 63 में स्वर्ण पदक जीता। पैरा एशियाई गेम्स 22 से 28 अक्तूबर तक चीन के हांगझू में आयोजित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- शैलेश कुमार बिहार के जमुई ज़िले के अलीगंज प्रखंड के इस्लामनगर के रहने वाले हैं।
- इससे पहले शैलेश ने जुलाई में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वहीं 16 से 20 मार्च, 2023 तक पुणे में आयोजित 21वीं पैरा एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था।
- इसके अलावा शैलेश ने भुवनेश्वर में 28 से 30 मार्च, 2022 तक आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था।

नोट :

बिहार के 15 शिल्प कलाकार वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 मेधा पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

25 अक्तूबर, 2023 को बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिवेशन भवन में हुए समारोह में राज्य के 15 शिल्प कलाकार को वर्ष 2021 के राज्य पुरस्कार और 14 को मेधा पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों को 50 हज़ार रुपए और मेधा पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 25 हज़ार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिये गए।
- इन कलाकारों का चयन राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ है। 15 नवंबर, 2021 से 24 दिसंबर, 2021 तक विभिन्न शिल्पों के लिये उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की ओर से प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें कुल 322 कलाकारों ने भाग लिया था।
- राज्य पुरस्कार (2021) से सम्मानित कलाकार:
  - अर्चना कुमारी (मधुबनी पेंटिंग), भगवान ठाकुर (मधुबनी पेंटिंग), अंबिका देवी (पेपर मेशी शिल्प), दीपेश सोनी (काष्ठ कला), स्वाति राज (मेटल शिल्प), राधा कुमारी (सिक्की कला), अभिषेक कुमार (चर्म कला), हिना कुमारी (मंजूषा पेंटिंग), चंद्रकांती देवी (एप्लिक शिल्प), सुमन सिंह (सुजनी कला), अनीता पांडेय (भोजपुरी आर्ट), ज्ञांति देवी (क्रोशिया), पूजा (टिकुली पेंटिंग), नमिता आज़ाद (अन्यान्य में कपड़े की गुड़िया शिल्प) एवं यशवंत कुमार झा (अन्यान्य में सिक्की कला)।
- मेधा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार:
  - आभा दास (मधुबनी पेंटिंग), मंजू करण (मधुबनी पेंटिंग), अमरेश कुमार लाल दास (मधुबनी पेंटिंग), रूबी देवी (मधुबनी पेंटिंग), रमा देवी (मधुबनी पेंटिंग), सुनील कुमार चौधरी (मंजूषा पेंटिंग), झना रानी (पेपरमेशी शिल्प), रूपा कुमारी (जूट शिल्प), मीना देवी (एप्लिक शिल्प), सुजाता कुमारी (सुजनी शिल्प), कौशिकी श्रीवास्तव (ब्लॉक पेटिंग), निक्की कुमारी (भोजपुरी आर्ट), सोनी (टिकुली पेंटिंग), एवं जितेंद्र राय (अन्यान्य में सिक्की कला)।

नोट :

बिहार में शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्कूल से कट गया लाखों बच्चों का नाम

चर्चा में क्यों ?

26 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के निर्देश के बाद कई ज़िलों के स्कूलों से लाखों बच्चों के नाम काट दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के निर्देश के बाद स्कूल से लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों के नाम भी काटे जा रहे हैं।
- अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया के तहत जुलाई से 24 अक्तूबर, 2023 तक पूरे राज्य से कक्षा एक से 12वीं तक के कुल 21 लाख 90 हज़ार 20 विद्यार्थियों के नामांकन रद्द कर दिये गए हैं।

नोट :

- सर्वाधिक 1,43,140 नामांकन पूर्वी चंपारण से रद्द किये गए हैं, वहीं न्यूनतम 13,237 नामांकन शेखपुरा ज़िले में रद्द हुए हैं।
- स्कूलों से कुल नामांकन रद्द होने वालों विद्यार्थियों की संख्या में कक्षा एक से आठ तक के अधिक विद्यार्थी हैं। इसमें कक्षा एक से आठ तक में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 18 लाख 28 हज़ार 859 तथा कक्षा नौ से 12वीं तक के तीन लाख 61 हज़ार 161 विद्यार्थी शामिल हैं।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन विद्यार्थियों के आगामी मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है।
- हालांकि, जिन विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया है, उन्हें दोबारा नाम दर्ज कराने का अवसर देने की व्यवस्था है, इसके लिये अभिभावक को नियमित स्कूल आने का शपथ-पत्र जमा कराना होगा।
- यदि किसी बच्चे का नामांकन कम उपस्थिति के कारण रद्द कर दिया गया है तो अभिभावक नियमित स्कूल आने का शपथ-पत्र जमा कराकर बच्चे का दोबारा नामांकन सुनिश्चित करा सकते हैं, लेकिन बच्चे के नियमित स्कूल नहीं आने की स्थिति में दोबारा नामांकन रद्द हो सकता है।

नामांकन रद्द वाले टॉप 10 जिले

पूर्वी चंपारण	-	1,43,140
पश्चिम चंपारण	-	1,34,451
वैशाली	-	1,10,182
मुजफ्फरपुर	-	1,04,065
पटना	-	97,369
दरभंगा	-	91,358
मधुबनी	-	87,212
समस्तीपुर	-	86,370
सीतामढ़ी	-	84,064
कटिहार	-	75,780
भागलपुर	-	74,279

इन जिलों में कम नामांकन हुए रद्द

शेखपुरा	-	13,237
लखीसराय	-	14,238
अरवल	-	18,455
शिवहर	-	20,449
कैमूर	-	24,420

नोट :

बिहार में इथेनॉल के लिये मक्का उत्पादन पर ज़ोर, 100 फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

26 अक्तूबर, 2023 को बिहार कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदेश में मक्के का रकबा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की योजना सभी ज़िलों में मक्के की खेती पर ज़ोर देना और 100 फीसदी हाइब्रिड बीज लगाना है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार कृषि विभाग के अनुसार, राज्य के सभी 38 ज़िलों में मक्का की खेती का क्षेत्र विस्तार करने की सरकार की योजना है। ज़्यादातर उत्तर और पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के किसानों के द्वारा सबसे अधिक मक्के की खेती की जाती है।
- विदित हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पटना में बिहार के चौथे कृषि रोडमैप (2023-2028) का शुभारंभ किया था, जिसमें इथेनॉल को बढ़ाने पर ज़ोर दिया था। इथेनॉल के उत्पादन बढ़ाने में मक्के की बड़ी भूमिका हो सकती है।
- बिहार सरकार ने रबी के मौसम में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से हाइब्रिड मक्के 'संकर'बीज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रबी में मक्के के बीज का 100 प्रतिशत हाइब्रिड बीज लगाने की तैयारी है। किसानों को इसके लिये बीज पर अनुदान के अलावा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।
- बिहार कृषि विभाग के अनुसार, राज्य में इस बार 1.50 लाख एकड़ क्षेत्र में मक्का की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 12 हज़ार क्विंटल तक मक्का उत्पादन का भी लक्ष्य तय किया जाएगा।
- कृषि विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को किसानों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया है।

नोट :

नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना मंज़ूर

चर्चा में क्यों ?

29 अक्तूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना को मंजूरी देते हुए इसे तीव्र गति से क्रियान्वित किये जाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- बिजली कंपनी द्वारा ब्रेडा के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन कराया जाना है। नहरों के किनारे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है।
- नहरों के किनारे एक कतार में बड़ी संख्या में सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना के लिये जल संसाधन विभाग ने बिजली कंपनी को इकठटे सूबे के सभी नहरों के लिये अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया है।
- बिजली कंपनी को अब अलग-अलग नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने के काम को लेकर पृथक् रूप से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी।
- बिजली कंपनी ने नहरों के किनारे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाए जाने की अपनी योजना पटना नहर के बिक्रम इलाके में शुरू करने की योजना बनाई थी। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था।
- इस प्रोजेक्ट के लिये सात से आठ महीने अंतर-विभागीय मंज़ूरी हासिल करने में लग गए। जल संसाधन विभाग ने इसके बाद इस शर्त के साथ बिजली कंपनी को मंज़ूरी प्रदान की है कि वह नहरों की सफाई के लिये जाने वाले वाहनों का रास्ता छोड़कर अपना काम करे। इस अनुमति के बाद पायलट प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा।
- बिजली कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलटी पर गुजरात की एक कंपनी से डीपीआर बनवाया हुआ है। गुजरात में यह मॉडल काफी सफल रहा है। सोलर प्लेट लगाए जाने को लेकर ज़मीन की समस्या नहर के किनारे एक सीध में ज़मीन मिलने की वजह से हल हो गई है।

नोट :

युवाओं को रोज़गार दिलाने में भागलपुर पूरे प्रदेश में शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

29 अक्तूबर, 2023 को बिहार के नियोजन विभाग ने सितंबर माह की प्रगति पर सभी ज़िलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार के युवाओं को रोज़गार दिलाने में भागलपुर पूरे प्रदेश में शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- भागलपुर को कुल प्राप्तांक 100 में शत-प्रतिशत अंक मिले, जबकि प्रदेश के अन्य पाँच ज़िलों कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली को भी 100 फीसदी अंक मिले हैं, लेकिन भागलपुर का लक्ष्य सबसे अधिक होने और लक्ष्य को पूरा कर लेने में सफल होने पर नंबर 1 स्थान दिया गया है।
- सहायक निदेशक (नियोजन) भरत जी राम ने बताया कि विभाग ने ज़िलों के परफॉर्मेंस का आकलन चार कैटेगरी में किया है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जॉब पाने वालों के रजिस्ट्रेशन में लक्ष्य को पूरा करने पर 30 अंक, करियर व वोकेशनल गाइडेंस में 20 अंक, जॉब कैंप लगाने में 30, निरीक्षण में 10 और निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने में 10 अंक निर्धारित किया गया था।
- इसमें भागलपुर ने एक हज़ार रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य के खिलाफ 1011 का निबंधन कराया। वोकेशनल गाइडेंस के लिये चार कैंप कराने का लक्ष्य था, पाँच कराए गए। करियर व पार्टिसिपेशन में 200 के लक्ष्य के खिलाफ 255 आए। रोज़गार देने के लिये 4 जॉब कैंप के लक्ष्य के खिलाफ नौ कराए थे। इसमें 105 में 105 को जॉब दिलाया गया। इसके अलावा इंस्पेक्टशन के दोनों अवयवों में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ।
- 38 ज़िलों की क्रमवार रैंकिंग: भागलपुर, कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, बक्सर, गोपालगंज, पटना, बेगूसराय, मोतिहारी, लखीसराय, दरभंगा, किशनगंज, जमुई, नवादा, मुंगेर, भोजपुर, शेखपुरा, सिवान, सुपौल कटिहार, खगड़िया, रोहतास, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेतिया, पूर्णिया, अरवल, मुज़फ्फरपुर, जहानाबाद, गया, शिवहर, बांका, अररिया और औरंगाबाद।

बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आवास देगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों ?

29 अक्तूबर, 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक लाख 22 हज़ार शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत् करीब 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि विद्यालय पहुँचने में लेट न हो।

नोट :

- बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के आवास के लिये ज़िला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गाँव तक मकान को किराए पर लिया जाएगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो भी सरकार लेगी।
- शिक्षा विभाग ने इच्छुक मकान मालिकों एवं रियल एस्टेट कंपनियों से पूछा है कि कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही कितने अगले एक-दो सालों में अतिरिक्त बनवा सकते हैं। इसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
- शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें 8 प्रतिशत, यानी लगभग 2500 रुपए करोड़ आवास के लिये खर्च किये जाते हैं।
- शिक्षा विभाग के अनुसार आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज़ पर लिये गए मकान और रियल एस्टेट कंपनियों को दिया जाएगा।
- शिक्षकों के दूरस्थ क्षेत्रों में आवास की सुविधा के लिये दो मॉडल पर शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, पहला मकान और बहुमंज़िला इमारत के मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वह कितने मकान किस ज़िले में, किस प्रखंड और ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से बने हुए हैं। शिक्षा विभाग उसे किराए पर तुरंत ले सकता है।
- दूसरा-रियल एस्टेट कंपनियों या अन्य इच्छुक ज़मीन मालिकों से ज़िला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में बहुमंज़िला इमारत एवं भवन निर्माण करने के लिये प्रस्ताव मांगा गया है। यहाँ केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। इन इमारतों को निजी कंपनियाँ अपने खर्चे पर बनाएंगी। शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय के लिये लीज़ पर लेगा और हर महीने किराया भुगतान करेगा।

मुज़फ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में खुलेगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मुज़फ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, जिसका काम अंतिम चरण में है।

प्रमुख बिंदु

- कौशल प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर व फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स व ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी, बैग निर्माण सहित 40 क्षेत्रों की ट्रेनिंग मिलेगी। एक साथ एक छत के नीचे एक हज़ार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
- यह केंद्र उत्तर बिहार सहित अन्य राज्यों के युवाओं को रोज़गार के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें निपुणता प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज एक में दिसंबर से फैंसी गारमेंट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। दिल्ली की एक गारमेंट कंपनी ने यहाँ फैक्ट्री स्थापित की है, जो दिसंबर से उत्पादन शुरू करेगी। इससे करीब एक हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे।
- विदित हो कि देश के बेरोज़गार युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। 2015 से 2016 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सफल संचालन के बाद 2016 में योजना का पार्ट-टू शुरू किया गया, जो 2020 तक चला। 2020 में इस योजना का पार्ट-थ्री शुरू किया गया। पार्ट-थ्री में करीब आठ लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

बिहार के शशि भूषण ने 37वें नेशनल गेम्स में जीता रजत पदक

चर्चा में क्यों ?

30 अक्तूबर, 2023 को गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के आरा ज़िले के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रण शंकरण ने बताया कि शशि भूषण ने 3 मिनट 41.49 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक जीता है।
- 20 वर्षों बाद नेशनल गेम्स के एथेलेटिक्स में बिहार को पदक मिला है। नेशनल गेम्स 2023 में बिहार के लिये यह दूसरा रजत पदक है। इसके पहले महिला रग्बी में बिहार एक रजत पदक अपने नाम कर चुका है।

नोट :

- गौरतलब है कि 25 अक्तूबर से 9 नवंबर तक गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसमें 22 विभिन्न खेल विधाओं में बिहार के 208 महिला और पुरुष खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के साथ बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के 15 अधिकारियों सहित कुल 223 लोगों ने हिस्सा लिया है।
- बिहार राज्य के खिलाड़ियों ने एथेलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाज़ी, तलवारबाज़ी, रग्बी, साइकिलिंग, जूडो, ताइक्वांडो, योगा, तैराकी, पेंचक सिलाट, सेपक टाकरा, भारोत्तोलन, वुशु, ट्राइथलॉन, मार्शल आर्ट, स्क्वैश, कुश्ती आदि प्रमुख खेलों में हिस्सा लिया है।
- नेशनल गेम्स के लिये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा यहाँ के खिलाड़ियों को विशेषरूप से प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिये अलग-अलग खेलों के विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए गए थे, जैसे- रग्बी और सेपक टाकरा के लिये आईआईटी बिहटा में, वुशु का मुज़फ्फरपुर में, तीरंदाज़ी का पाटलिपुत्र खेल परिसर में विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था।

कॉर्डियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई का दो दिवसीय 29वाँ वार्षिक सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

28-29 अक्तूबर, 2023 तक कॉर्डियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई के दो दिवसीय 29वें वार्षिक सम्मेलन का होटल मौर्या में आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से हृदय रोग विशेषज्ञ शामिल हुए थे।
- सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पी.एम.सी.एच.) को 5462 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश अस्पताल बनाया जा रहा है, ताकि मरीज़ों का इलाज और बेहतर ढंग से हो सके।
- निश्चय-2 में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जन्म से हृदय में छेदवाले बच्चों का नि:शुल्क इलाज करवाया जाता है। पटना में ही अब इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। आई.जी.आई.सी. में 198 बच्चों का और आई.जी.आई.एम.एस. में 24 बच्चों का इलाज हो चुका है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं। कई अस्पतालों का और विस्तार किया जा रहा है। आई.जी.आई.एम.एस. पटना में 2500, एन.एम.सी.एच. पटना में 2500, एस.के.एम.सी.एच, मुज़फ्फरपुर में 2500 बेड, डी.एम.सी.एच दरभंगा में 2500 बेड का विस्तार किया जा रहा है।
- राजवंशी नगर अस्पताल को हड्डी रोग के इलाज का विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है, जिसका नामकरण लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल किया गया है। आँख के लिये राजेंद्र नगर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है। डायबिटीज के लिये न्यू गार्डिनर अस्पताल को विशिष्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी स्व. रामबहादुर सिंह और स्व. पद्मानंद सिंह 'ब्रह्मचारी' की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण

चर्चा में क्यों ?

27 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा ज़िले के पंचगछिया ग्राम के भगवती प्रांगण में 'कोसी का गांधी 'स्वातंत्र्यवीर स्व. रामबहादुर सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्व. पद्मानंद सिंह 'ब्रह्मचारी 'की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रामबहादुर बाबू का जन्म 1901 ई. में हुआ था और उनकी मृत्यु 1950 ई. में हुई थी। 1919 ई. में रामबहादुर बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती के संपर्क में आए और अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए काले कानून 'रॉलेट एक्ट 'का विरोध करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिये रामबहादुर बाबू ने 1920 ई. में सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर कोसी सेवक दल का गठन किया और कोसी क्षेत्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तथा खादी ग्राम उद्योग की शुरुआत की।
- 1925 ई. में जब गांधीजी बिहार आए थे और पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज आदि जगहों पर गए तो भ्रमण के दौरान रामबहादुर बाबू उनके साथ रहे थे। 1930 ई. में उन्होंने गांधीजी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया।
- वर्ष 1934 ई. में जब बिहार में भूकंप आया था और गांधीजी भूकंप पीड़ितों से मिलने मुंगेर पहुँचे थे तो पंचगछिया ग्राम भी आकर रामबहादुर बाबू से मिले थे, क्योंकि इनका घर भी भूकंप में ध्वस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में भी रामबहादुर बाबू की धर्मपत्नी कुंती देवी ने अपना धन बापू के समक्ष दान में दे दिया था, ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। 1942 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन में भी रामबहादुर बाबू ने सक्रिय भूमिका निभाई थी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रामबहादुर बाबू के पुत्र पद्मानंद सिंह 'ब्रह्माचारी 'ने भी 1942 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। पद्मानंद सिंह का जन्म वर्ष 1921 में और मृत्यु वर्ष 2016 में हुई थी।

नोट :